

एयरपोर्ट का बढ़ सकता है दायरा, जमीन का होगा अधिग्रहण

बनेगा एविएशन इंडस्ट्री हब, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा

● भविष्य में बड़ी कंपनी आ सकती है, इसको देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी गई : सीईओ

पार्यनियर समाचार सेवा | नोएडा



यूपी की योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में नजदीक बन रहे जेवर एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाने के बारे में चिनार कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के दायरे को बड़ा करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1200 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकरण की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

सरकार से हरी झंडी मिलते ही जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी। बताया जाता है कि अधिग्रहण की ओर से जमीन एविएशन इंडस्ट्री हब अधिग्रहित हो चुकी है। इसमें एयरपोर्ट का विकसित करने के लिए सात गांवों की जमीन निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।

एयरपोर्ट के निकट एविएशन इंडस्ट्री हब अधिग्रहित हो चुकी है। इसमें एयरपोर्ट का जाता है। एयरपोर्ट के अलग-अलग चरणों के लिए अब तक 6554 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। एयरपोर्ट के हब का भी बड़ा केंद्र बनेगा। जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

सरकार के प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा

इसके बाद एयरपोर्ट का क्षेत्र 7754 हेक्टेयर हो जाएगा। दरअसल, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने से गोपीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां यहाँ निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां के अनेकी ज्यादा संभावना है। उम्मीद है कि भविष्य में एयरबस जैसी कोई बड़ी कंपनी आ सकती है।

इसके देखते हुए प्राधिकरण घटले से ही जमीन सुरक्षित कर लेना चाहता है। जमीन अधिग्रहण कर नायल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। चौराली, अहमदपुर, मंगलपुर, सुदुल्लापुर, अलावलपुर, देवरार व भूमिकारा आदि गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

अथारिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 1200 हेक्टेयर जमीन और अधिग्रहित की जाएगी। इसमें एविएशन हब का विस्तार होगा। भविष्य में कोई भी बड़ी कंपनी आ सकती है। इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

थादी से पहले होटल में मिली लड़की की लाश, हड़कंप

● दोष्ट के साथ ठहरी थी, आरोपी फुटर

पार्यनियर समाचार सेवा | गाजियाबाद

गाजियाबाद के एक होटल में रविवार सुबह 23 साल की लड़की की लाश मिली। लड़की के दोस्त ने उनके भाई को फोन करके घटना के बारे में बताया। उन्हें कहा कि तुम्हारी बहन होटल में मरी पड़ी है। उसे अकर ले जाओ। इसके बाद अनन्त-फानन में घरवाले होटल पहुंचे।

देखा जाए तो लड़की का शव कमरे में बेड पर पड़ा था। उसके नाक से ज्ञान निकल रहा था। मगर सूचना देने वाले दोस्त वहाँ से फरार था। इसके बाद जब कमरा खोला गया तो शहजादी की लाश बेड पर पड़ी थी। बुलाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमर्टम के लिए भेज दिया और दोस्त की तबाया चल रही है।

इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई। अथारिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 1200 हेक्टेयर जमीन और अधिग्रहित की जाएगी। इसमें एविएशन हब का विस्तार होगा। भविष्य में कोई भी बड़ी कंपनी आ सकती है। इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

नोएडा में लगाए जाएंगे 1600 कैमरे, कंपनी देगी सर्वे रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बताया कि बर्तमान में नोएडा में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ट्रैफिक कैमरे जैसे सेटिंस सिस्टम के जरिए 1046

कैमरे से शर कर लिए जाएंगे। इन्हें निरापत्ती की जा रही है।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। ऐसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन के बालों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। जबकि सेफ स्टीटी पुलिस की 24 घंटे निरापत्ती में नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा।

चालान के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। कैमरे से यातायात वालों के लिए इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन के अंदर इस्तेमाल कर दिया जाएगा।

पुलिस ने तेज आसानी से पकड़ा भालान के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा।

जबकि सेफ स्टीटी पुलिस के पास पहले से हो रहा है। एसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन पर तहत 1600 कैमरे परीक्षण के बाद जब कमरा खोला जाएगा।

इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

नोएडा के अलग से कैमरे लगाए जाएंगे। लगाए जाने कैमरों में फेस डिडक्शन कैमरे भी शामिल हैं।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। ऐसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन पर तहत 1600 कैमरे परीक्षण के बाद जब कमरा खोला जाएगा।

इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

नोएडा के अलग से कैमरे लगाए जाएंगे। इस माले में अजात चोरों के खिलाफ केस दर्करा कराया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि वर्तमान में नोएडा में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ट्रैफिक कैमरे जैसे सेटिंस सिस्टम के जरिए 1046

कैमरे से शर कर लिए जाएंगे। इन्हें निरापत्ती की जा रही है।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। ऐसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन पर तहत 1600 कैमरे परीक्षण के बाद जब कमरा खोला जाएगा।

इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

नोएडा के अलग से कैमरे लगाए जाएंगे। इस माले में अजात चोरों के खिलाफ केस दर्करा कराया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि वर्तमान में नोएडा में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ट्रैफिक कैमरे जैसे सेटिंस सिस्टम के जरिए 1046

कैमरे से शर कर लिए जाएंगे। इन्हें निरापत्ती की जा रही है।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। ऐसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन पर तहत 1600 कैमरे परीक्षण के बाद जब कमरा खोला जाएगा।

इसके देखते हुए घटले से ही तैयारी कर ली गई है।

जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है।

नोएडा के अलग से कैमरे लगाए जाएंगे। इस माले में अजात चोरों के खिलाफ केस दर्करा कराया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि वर्तमान में नोएडा में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ट्रैफिक कैमरे जैसे सेटिंस सिस्टम के जरिए 1046

कैमरे से शर कर लिए जाएंगे। इन्हें निरापत्ती की जा रही है।

बदमाशों का डेटा पुलिस के पास पहले से हो रहा है। ऐसे में कोई भी बदमाश यह इन कैमरों की जड़ में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरी डेटा कोटेल रूम में दिखाई देगा।

जिसके द्वारा लोकेशन पर तहत 1600 क

गाजा में सहायता इजराइल की सहमति

गाजा में मानवीय सहायता पर आधिकारक दुनिया के दबाव के आगे इजराइल को झुकना पड़ा। इजराइल-हमास टकराव शुरू होने के लगभग दस दिन बाद तक उसके निवासियों को भयानक हिंसा, दवाओं की कमी तथा पानी व भोजन जैसी मूलभूत ज़रूरतों के संकट का समाप्त करना पड़ा। आधिकारकों कुछ मानवीय सहायता गाजा पहुंचे लगी है जिससे वहाँ के निवासियों को थोड़ी राहत मिली है जिसकी उनको बहुत आवश्यकता थी। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू की इस स्पष्ट घोषणा के बाद चित्रत बहुत खतरनाक हो गई थी कि गाजा में बाहर से कोई सहायता नहीं आने दी जाएगी। अब आधिकारक सारी दुनिया व अधिकारियों ने इस स्पष्ट घोषणा के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कठोर दृष्टिकोण अपनाने के बाद गाजा के निवासियों तक मानवीय सहायता पहुंच रही है, हालांकि यह अब भी बहुत कम है। स्वच्छ जल, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्यका तक समित पहुंच के कारण गाजा की जनता एक अन्य निराशा के दुखिका में फंसी है। अभी उद्धवारिया लागू होने में थोड़ा विलम्ब है, परन्तु मानवीय सहायता की शुरूआत इस संकट से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सकारात्मक संकेत है। भारत समेत अनेक देशों, गैर-सरकारी संगठनों व संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में जनता के कष्ट दूर करने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं।

अल-अहाल अप्यताल पर भयानक हमले ने विश्व समुदाय की चेतना झकझोर दी है। वास्तव में इस समय सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता है जिसे प्राप्त करना कठिन हो गया है। गाजा का एकमात्र केंसर अस्पताल किसी समय बंद हो सकता है ब्यांकिं उसके पास ईंधन व दवायें समाप्त हो रही हैं।

अब सप्लाई लाने वाले डब्लूएचओ के ट्रक ऐसे में बहुंच में बहुंच बताते हैं। भले ही यह वह महत्वपूर्ण हो, पर डब्लूएचओ ने इसे 'आवश्यकता के समुद्र में एक बूँद' बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्लूएचओ ने कहा है कि दवाओं से भी पाच ट्रक गाजा और मिस्र के बीच सीमा पर गाजा में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अभियानी राष्ट्र प्रति किलो 2,3 रुपये किलो लिया है।

बाइडेन की तेलअबीव यात्रा का प्रत्यक्ष परिणाम है। इजराइल और मिस्र के नेताओं से 'स्टॉ' चर्चा के बाद बाइडेन ने गाजा में प्रवेश की अनुमति पर समझौते का खुलासा किया था। इजराइल ने सैनिक कार्रवाई जारी रखते हुए भी इस व्यवस्था पर सहमति जताई थी। इजराइल द्वारा धैर्यबंद गाजा पहुंच की 'संपूर्ण नाकेबंदी' की घोषणा के बाद यह पहली सप्लाई है। गाजा में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। हमास अंतर्कांतों द्वारा 1000 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल को इजराइली क्षेत्र पर हमले में कम से कम 1400 लोग जारी रखते हुए अनाजों के लिए क्रमशः 2,3 व 1 रुपया किलो लिया है।

लाभार्थी दो प्रकार के हैं। अंत्योदय अन योजना-एवार्वाई के अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीबों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज दिया जाता है। एप्रिल, 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा असाधारण स्थितियों को क्रमशः 2,3 व 1 रुपया किलो लिया है।

लाभार्थी दो प्रकार के हैं। अंत्योदय अन योजना-एवार्वाई के अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीबों को प्रति परिवार प्रति माह 164 मिलियन परिवारों को एक किलो दाल 'मुफ्त' दी जाती है। शुरूआत में यह योजना तीन माह के लिए थी, पर इस एप्रिल के अंतर्गत 24 मिलियन परिवार हैं तथा प्रति माह 2,3 व 1 रुपये किलो पर 7 किलो अनाज पाने वाले लोगों की संख्या 16 साल से लागू नाकेबंदी के कारण धैर्यबंद गाजा पहुंच की घोषणा के बाद यह पहली सप्लाई है। गाजा में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। हमास अंतर्कांतों द्वारा 1000 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल द्वारा धैर्यबंद नाकेबंदी से बिजली सप्लाई बाधित होने के साथ ही भोजन एवं ईंधन के प्रवाह में बाधा आई थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दी थी जहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या इजराइल द्वारा 16 साल से लागू नाकेबंदी के कारण धैर्यबंदी की शिकाया है। गाजा में मानवीय सहायता की यह गति जारी रहनी चाहिए तथा टकराव के मूल राजनीतिक मुद्दों के समाधान हेतु राजनीतिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए। वर्तमान विपरीत स्थितियों को देखते हुए आशा की यह किरण एक उत्तरक की भूमिका अदा करते हुए गाजा के लोगों को थोड़ी राहत देंगे। इसके विश्व समुदाय को एक अवसर मिलेगा कि वह गाजा का यथार्थ समझ तथा यहाँ रहने वाले नागरिकों का शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयास करे।

खाद्य सब्सिडी की समीक्षा जरूरी

खाद्य सब्सिडी योजना क्रियान्वयन के अधिकांश कार्य बदलते समय के अनुकूल नहीं हैं। इसके कारण चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसकी समीक्षा की जरूरत है।

उमर गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक)
हैं

नीति आयोग ने केन्द्रीय समन्वय एजेंसी पर विचार किया है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सब्सिडी योजना की प्रभावशीलता का अंकलन कर सके। एजेंसी को योजना को बहरत बनाने के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब आधिकारक सारी दुनिया व अधिकारियों ने विश्व समय द्वारा धैर्यबंद नाकेबंदी से संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में जनता के कष्ट दूर करने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं।

अल-अहाल अप्यताल पर भयानक हमले ने विश्व समुदाय की चेतना झकझोर दी है। वास्तव में इस समय सहायता की शुरूआत इस संकट से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सकारात्मक संकेत है। भारत समेत अनेक देशों, गैर-सरकारी संगठनों व संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में जनता के कष्ट दूर करने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं।

अल-अहाल अप्यताल पर भयानक हमले ने विश्व समुदाय की चेतना झकझोर दी है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सकारात्मक संकेत है। भारत समेत अनेक देशों, गैर-सरकारी संगठनों व संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में जनता के कष्ट दूर करने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं।

लाभार्थी दो प्रकार के हैं। अंत्योदय अन योजना-एवार्वाई के अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीबों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमप्सी पर खाद्यान् खारीदने तथा उनको स्टोर अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 197,000 करोड़ रुपये संकेत देता है।

करोड़ तथा 2023-24 में बजट अनुमति के अनुसार 197,000 करोड़ रुपये होंगा। कुल मिला कर यह 1385,000 करोड़ रुपये होता है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना-एवार्वाई को एक नाकेबंदी के अंतर्गत सस्ता खाद्यान् रुपये भी शामिल है। अप्रैल, 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा असाधारण स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री एमप्सीके वर्ष के अंतर्गत सस्ता खाद्यान् रुपये भी शामिल है। अप्रैल, 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा असाधारण स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री एमप्सीके वर्ष के अंतर्गत सस्ता खाद्यान् रुपये भी शामिल है।

करोड़ तथा 2023-24 में बजट अनुमति के अनुसार 197,000 करोड़ रुपये होंगा। कुल मिला कर यह 1385,000 करोड़ रुपये होता है। 2015 में आई शांति की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह वह सुझाव देता है कि जनसंख्या के अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमप्सी पर खाद्यान् खारीदने तथा उनको स्टोर अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 197,000 करोड़ रुपये संकेत देता है।

करोड़ तथा 2023-24 में बजट अनुमति के अनुसार 197,000 करोड़ रुपये होंगा। कुल मिला कर यह 1385,000 करोड़ रुपये होता है। 2015 में आई शांति की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह वह सुझाव देता है कि जनसंख्या के अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमप्सी पर खाद्यान् खारीदने तथा उनको स्टोर अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 197,000 करोड़ रुपये संकेत देता है।

करोड़ तथा 2023-24 में बजट अनुमति के अनुसार 197,000 करोड़ रुपये होंगा। कुल मिला कर यह 1385,000 करोड़ रुपये होता है। 2015 में आई शांति की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह वह सुझाव देता है कि जनसंख्या के अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमप्सी पर खाद्यान् खारीदने तथा उनको स्टोर अनुसार एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो एक नाकेबंदी के अंतर्गत वर्ष के अन्य योजना-एवार्वाई को प्रति परिवार प्रति माह 197,000 करोड़ रुपये संकेत देता है।

करोड़ तथा 2023-24 में बजट अनुमति के अनुसार 197,000 करोड़ रुपये होंगा। कुल मिला कर यह 1385,000 करोड़ रुपये होता है। 2015 में आई शांति की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह वह सुझाव देता है कि जनसंख्या के अनुसार एक नाकेबंदी

